नईदुनिया

ईरान का कड़ा रुख, लेबनान पर हमला बंद होगा तब होगी अमेरिका से अंतिम समझौते पर सीधी वार्ता

दोहा/वाशिंगटन

कतर की राजधानी दोहा में अमेरिकी और ईरानी वार्ताकार मौजूद हैं। दोनों पक्षों के बीच अब तक सीधी वार्ता शुरू नहीं हो सकी है। ईरान ने अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए कड़ी शर्त रखी है। ईरान का कहना है कि अगर लेबनान में इजराइली हमले रुक जाएं (युद्ध खत्म हो जाए) तो उसे वार्ता शुरू करने पर कोई परहेज नहीं है। इस बीच अमेरिकी वार्ताकारों ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री से मुलाकात की है।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर घालीबाफ ने कहा कि तेहरान अंतिम समझौते पर बातचीत तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक लेबनान में लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। साथ ही वार्ता शुरू करने से पहले वाशिंगटन को तेल पर लगे प्रतिबंध हटाते हुए ईरान के फ्रीज किए गए फंड को जारी करना होगा। ईरान के इस रुख की वजह से दोहा में अमेरिकी वार्ताकारों से सीधी बातचीत संभव नहीं हो पा रही है। अलबत्ता

कतर के प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने दोहा में अमेरिकी दूत स्टीव विटकाफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की है।

ईरानी वार्ताकार भी दोहा में मौजूद हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच आमने-सामने की बातचीत शुरू होने के कोई संकेत नहीं हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि वह अमेरिका के साथ हुए एमओयू को लागू करने और फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति को जारी करने के मुद्दे पर मध्यस्थ कतर के जरिए अप्रत्यक्ष बातचीत करेगा। तेहरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका युद्ध खत्म करने के समझौते का उल्लंघन करता है, तो वह उसका जवाब देगा। इजराइल ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक और लड़ाके को मार गिराया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ स्काट उहलिंगर का कहना है कि वाशिंगटन होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ते तनाव को संभालने के लिए दोहा में ईरान के साथ अप्रत्यक्ष तकनीकी बातचीत कर रहा है। उहलिंगर ने कहा मुझे लगता है कि अमेरिकी वार्ताकारों का मुख्य मकसद तकनीकी समस्या को सुलझाना है, ताकि भविष्य में आने वाली कुछ मुश्किलों को टाला जा सके।

सीआईए के पूर्व अधिकारी उहलिंगर ने कहा कि ये मुश्किलें होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण पाने की ईरान के राजनयिक कदमों से जुड़ी हैं। अमेरिका यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि एमओयू के अनुसार, जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा हो। उहलिंगर ने कहा कि वाशिंगटन की कोशिश है कि कतर और अन्य खाड़ी देश ईरान के साथ बातचीत करके एक गठबंधन बनाएं, जो इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने वाले यातायात को नियंत्रित कर सके।

न्यूज ब्रीफ

अमेरिका, ईरान ने लेबनान डी-कान्फ्लिक्शन सेल के लिए दूत नियुक्त किएः घालीबाफ

तेहरान। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर घालीबाफ का कहना है कि अमेरिका और ईरान ने

लेबनान डी-कान्फ्लिक्शन सेल (टकराव रोकने वाली इकाई) के लिए दूत नियुक्त किए हैं। इन दूतों का प्राथमिक उद्देश्य दो विरोधी या अलग-अलग ताकतों के बीच गलतफहमी को रोकना, सैन्य टकराव को टालना और आपसी सहयोग या युद्धविराम को बनाए रखना है। यह नियुक्तियां स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टाक में अमेरिका और ईरान के बीच हुई ऐतिहासिक वार्ता के दौरान लेबनान में तनाव कम करने और युद्धविराम का पालन कराने के लिए एक विशेष लेबनान डी-कान्फ्लिक्शन सेल के गठन पर सहमति बनने के बाद की गई हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी संसद के अध्यक्ष ने सरकारी प्रेस टीवी को दिए साक्षात्कार में यह दावा किया। उन्होंने कहा ईरान और ओमान पहले ही होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सेवाओं के प्रशासन से जुड़े सभी कानूनी और सेवा संबंधी मामलों पर समझौते पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक एमओयू की पांच शर्तों को लागू नहीं किया जाता। इन शर्तों में लेबनान में युद्ध को रोकना, ईरानी तेल एक्सपोर्ट को सुरक्षित करना और ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करना शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि ईरान-अमेरिका एमओयू का मकसद लेबनान की आजादी को बनाए रखना है। घालीबाफ का कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान की ताकत का सबसे बड़ा जरिया है। उन्होंने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी संप्रभुता बनाए रखेगा। एमओयू से इस जलमार्ग में समुद्री सेवाओं के शुल्क से केवल 60 दिनों की अस्थायी छूट मिलती है। प्रेस टीवी की वेबसाइट के अनुसार, संसद के अध्यक्ष ने कहा, ये हमारे क्षेत्रीय जल क्षेत्र हैं हम अमेरिका को यह दावा करके विवाद या गलत तर्क पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य का सैन्यीकरण किया है। ईरान किसी भी हालत में इस रुख से पीछे नहीं हटेगा।

ईरान, हमास, हिजबुल्लाह से लड़ाई कभी खत्म नहीं होगीः नेतन्याहू

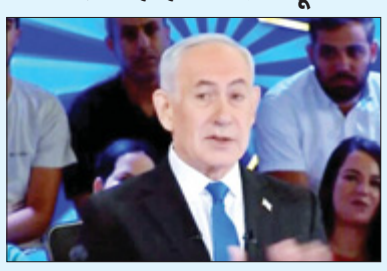

तेल अवीव। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि ईरान और उसके सहयोगियों (हमास और हिजबुल्लाह) के खिलाफ पूरी जीत हासिल करने की उनकी कोशिश कभी खत्म नहीं होगी । उन्होंने पिछले तीन साल में इजराइल की सैन्य उपलब्धियों का जिक्र किया और साथ ही यह भी कहा कि अभी और काम करना बाकी है। द टाइम्स आफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने चैनल 14 को दिए साक्षात्कार में यह दावा किया। नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या गाजा युद्ध के दौरान पूरी जीत हासिल करने का उनका वादा अभी भी कायम है। नेतन्याहू ने कहा, यह कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उसने अपने दुश्मनों को काफी कमजोर किया है। प्रधानमंत्री ने हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के ज्यादातर नेताओं को मारने और गाजा, लेबनान व सीरिया में बफर जोन बनाने के अपने कदमों की तारीफ की। उन्होंने यह माना कि ईरान के साथ युद्ध के नतीजे उन पक्के लक्ष्यों से कमतर रहे जो उन्होंने शुरू में तय किए थे।

आजादी की चाह में 40 घंटे का मौत से मुकाबला, जिनपिंग के दुश्मन डोंग गुआंगपिंग की कहानी

बीजिंग। आजादी की कीमत कभी-कभी जेल नहीं, बल्कि जान जोखिम में डालकर भी चुकानी पड़ती है,

और चीन के 68 वर्षीय लोकतंत्र समर्थक डोंग गुआंगपिंग की कहानी इसका जीवंत प्रमाण है। शी जिनपिंग के कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ मुखर आवाज उठाने वाले डोंग ने एक छोटी सी रबर की नाव में बैठकर करीब 40 घंटे तक समुद्र में मौत से मुकाबला किया। इस दौरान उनके मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने वाली थी, चारों तरफ सिर्फ पानी था और उन्हें यह भरोसा भी नहीं था कि अगला सूरज देख पाएंगे या नहीं। लेकिन उनके मन में एक ही बात थी, चीन में जिस तरह जी रहा था, उससे तो मौत भी बेहतर लग रही थी। यही अटल संकल्प उन्हें आखिरकार कनाडा तक ले आया, जहाँ पहुँचकर उन्होंने एक दशक बाद पहली बार खुद को सचमुच आजाद महसूस किया। कनाडा पहुँचने के बाद डोंग ने कहा कि चीन में रहना पिंजरे में कैद रहने जैसा था। उन्होंने बताया कि वहाँ अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है और जेल से रिहा होने के बाद भी पुलिस लगातार उनकी निगरानी करती थी, जिससे सामान्य जीवन जीना असंभव था।

चीन हुआ कटहल का दीवाना, बांग्लादेश से कर रहा करार, पीएम तारिक रहमान की हाल ही में चीन यात्रा पर हुई कृषि व्यापार पर चर्चा

ढाका

चीन में कटहल की मांग बढ़ती जा रही है। भारत-बांग्लादेश श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के स्थानीय बाजार में बिकने वाला कटहल अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बन गया है। वियतनाम से बड़े पैमाने पर कटहल आयात करने के बाद अब चीन बांग्लादेश से बड़ा करार करने जा रहा है। इससे कटहल एक बार भी कृषि व्यापार की चर्चा के केंद्र में आ गया है। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान हाल ही में चीन यात्रा पर गए थे। यहां दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष तौर पर अगर किसी चीज पर बात हुई तो वह कटहल और चीनी ही थी। फिलहाल चीन की ओर से प्रस्ताव दिया गया और गुणवत्ता मानकों को सेट किया जा रहा है, जिसका साफ संकेत है कि बांग्लादेश को चीन कटहल के बड़े आपूर्तिकर्ता के तौर पर देख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश दुनिया के प्रमुख कटहल उत्पादक देशों में शामिल है।

हालांकि इसका बड़ा हिस्सा देश में ही खप जाता है - चीन में कटहल के अलावा जिस फल की ज्यादा मांग है वो नारियल है। रिपोर्ट में एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है कि कटहल दो वजहों से अलग है। पहला यह मीठे फल के तौर पर खाया जा सकता है। दूसरा इसे शाकाहारी मीट के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से प्लांट बेस्ड फूड इंडस्ट्री में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। 2025 में वियतमानी कटहल के चीन को निर्यात किए जाने को औपचारिक मंजूरी दी गई थी। चीन के सीमा शुल्क प्रशासन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम में तकरीबन 84 हजार से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में कटहल की खेती होती है। अगर सालाना उत्पादन देखें तो यह 10 लाख टन से ज्यादा है। 2024 में ही वियतनाम ने कटहल निर्यात से तकरीबन 146 मिलियन डालर की कमाई की थी। चीन के लिए ये अच्छा इसलिए भी है, क्योंकि दोनों देशों भागौलिक तौर पर एक दूसरे से निकट हैं। इससे परिवहन लागत कम रहती है और कटहल के जल्द ही खराब होने की संभावना भी न के बराबर होती है। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े कटहल उत्पादकों में से एक है। यहां सालाना 10 से 12 लाख टन कटहल का उत्पादन होता है। कटहल को पोषण के लिहाज से बेहद खास माना जाता है।

नक्शे पर बिंदी जितना छोटा देश, पर कांपते हैं भारत के दुश्मन

विक्टोरिया। हिंद महासागर में चीनी प्रभुत्व के दिन अब शायद लदने वाले हैं, क्योंकि भारत ने समुद्री क्षेत्र में ड्रैगन को घेरने के लिए अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विजन महासागर के तहत सीधे सेशेल्स पहुंचे हैं, जिसे हिंद महासागर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक खिलाड़ी माना जाता है। पिछले कई वर्षों से चीन इस क्षेत्र के छोटे द्वीपीय देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर सैन्य अड्डे स्थापित करने की फिराक में था, जैसा कि उसने श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट के साथ किया। लेकिन भारत ने ऐन वक्त पर सेशेल्स के साथ अपने सुरक्षा और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करके चीन के स्ट्रिंग आफ पर्ल्स प्लान को बड़ा झटका दिया है। अब हिंद महासागर के उस व्यस्त समुद्री मार्ग पर, जहां से दुनिया का सबसे अधिक तेल और व्यापार गुजरता है, भारत और सेशेल्स मिलकर चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी करेंगे। इस साझा निगरानी के बाद हिंद महासागर में चीन की मनमानी पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा, और ड्रैगन की किसी भी संदिग्ध गतिविधि का भारत तुरंत और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। मालदीव के एक बार फिर चीन के खेमे में चले जाने के बाद, भारत के लिए सेशेल्स का साथ रणनीतिक रूप से और भी अधिक नाजुक और महत्वपूर्ण हो गया है। यही कारण है कि दिल्ली से रवाना होते समय प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सेशेल्स भारत का एक अमूल्य समुद्री पड़ोसी है, जो विजन महासागर और ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट करने की भारत की मुहिम का सबसे मजबूत स्तंभ है। नक्शे पर एक बिंदी जितना छोटा दिखने वाला सेशेल्स आखिर भारत और चीन जैसी महाशक्तियों के बीच एक प्रमुख रणनीतिक अखाड़ा क्यों बना हुआ है दरअसल, भौगोलिक आकार में भले ही यह देश बेहद छोटा हो, लेकिन समुद्री मार्ग के संदर्भ में इसकी कूटनीतिक अवस्थिति इसे हिंद महासागर का सबसे बड़ा किंगमेकर बनाती है। यह खूबसूरत द्वीपीय देश दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त समुद्री मार्ग के ठीक मुहाने पर एक पहरेदार की तरह स्थित है, जहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले तेल के विशाल टैंकर गुजरते हैं।

अमेरिका में दीपावली पर जारी होगा डाक टिकट

वाशिंगटन

अमेरिकी डाक सेवा (यूएस पोस्टल सर्विस) ने इस साल हिन्दू त्योहार दीपावली पर डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। इसमें ह्यूस्टन में रहने वाली संगीता भूटाडा की बनाई रंगोली की आकृति है। यूएस पोस्टल सर्विस की वेबसाइट पर यह घोषणा 29 जून को की गई। विवरण के अनुसार, दीपावली हिन्दू कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। शरद ऋतु में मनाया जाने वाला यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व आमतौर पर पांच दिन तक मनाया जाता है।

इस साल दीपावली 8 नवंबर को मनाई जाएगी। संगीता भूटाडा की रंगोली की फोटो विजय दीक्षित ने ली थी।

वेबसाइट के अनुसार, संगीता भारत की रहने वाली हैं और लंबे समय से ह्यूस्टन इलाके में रह रही हैं। वे लगभग 30 वर्ष से इस प्राचीन लोककला का अभ्यास कर रही हैं। इस डाक टिकट को जेनिफर अर्नोल्ड ने डिजाइन किया है। इसे अक्टूबर में जारी किया जाएगा।

यूएस पोस्टल सर्विस ने अमेरिकी तटरक्षक बल, क्रिसमस कुकीज, यहूदियों के त्योहार हनुक्का और अफ्रीकी-अमेरिकी संस्कृति के उत्सव क्वांजा पर आधारित डाक टिकट जारी करने की भी घोषणा की है। कहा गया है कि अमेरिकी तटरक्षक बल अकादमी की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर भी एक डाक टिकट जारी किया जाएगा।

इसके अलावा यहूदियों के त्योहार हनुक्का पर लगातार नौवें साल डाक टिकट जारी करने की घोषणा की गई है। इस बार के डाक टिकट में ड्रेडल (एक तरह का लट्टू) का डिजिटल चित्र है। यह कलाकार लिसा पेरिन की यहूदी विरासत और पूर्वी यूरोपीय लोककला परंपरा को दर्शाता है।

पत्नी को पहाड़ से धक्का देकर मारा, इंश्योरेंस के पैसे पर 20 साल किया ऐश

वाशिंगटन। अमेरिका में करीब 20 साल पुराने चर्चित मामले का अंत हो गया है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पहाड़ से धक्का देकर मार दिया था। बाद में इंश्योरेंस के पैसे से 20 साल तक मौज की जिंदगी जीता रहा, लेकिन उसका एक पुराना पाप सामने आ गया, जिसने उसकी पत्नी की हत्या का मामला खोल दिया। हत्या के मुकदमे की सुनवाई शुरू होने से पहले ही व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों की मानें तो उसकी मौत खुद को पहुंचाई चोट के चलते हुई। इसके बाद मृतक पत्नी के माता-पिता ने कहा कि उन्हें दामाद की मौत से मानसिक शांति मिल गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला 2006 का है। 29 साल की बर्नैडेट वेंडर मीर अपने पति डेविड वेंडर मीर के साथ यूटा के मशहूर जियोन नेशनल पार्क घूमने गई थीं। वहीं एंजेल्स लैंडिंग नाम की खतरनाक चट्टान से गिरकर उनकी मौत हो गई। उस समय इसे हादसा माना गया था, लेकिन साल 2022 में एक महिला के नए खुलासे के बाद पुलिस ने जांच दोबारा शुरू की।

चीन को टक्कर देने की क्षमता रखता है भारत भारतीय प्रतिभा का लोहा मानता है अमेरिका

वाशिंगटन

भारत की तकनीकी क्षमता और इंजीनियरिंग प्रतिभा को लेकर अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उसने भारत को वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में एक असाधारण शक्ति के रूप में रेखांकित किया है। अमेरिका के आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इंजीनियरिंग वर्कफोर्स और टैलेंट के मामले में भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो चीन को वास्तविक चुनौती देने की क्षमता रखता है। यह बयान भारतीय प्रतिभा के विश्वव्यापी प्रभाव और स्वीकृति को दर्शाता है। वाशिंगटन में आयोजित एक लीडरशिप समिट में हेलबर्ग ने भारत की विशाल इंजीनियरिंग प्रतिभा, तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी इकोसिस्टम और मजबूत होती अर्थव्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन्हीं कारणों से भविष्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक और अत्याधुनिक इनोवेशन के विकास में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

हेलबर्ग के अनुसार, भारत का तकनीकी इकोसिस्टम तेजी से परिपक्व हो रहा है और विभिन्न तकनीकी प्रयोगों के विकास में देश उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि नई तकनीकों को आम लोगों

तक पहुँचाने में भारत की भूमिका बेहद अहम साबित होगी, जिससे वैश्विक स्तर पर तकनीकी पहुँच और समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। हेलबर्ग ने भारत को नई पीढ़ी की तकनीकी सेवाओं के लिए सबसे आकर्षक बाजार भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत की बड़ी आबादी, विशाल इंजीनियरिंग वर्कफोर्स और तीव्र आर्थिक विकास मिलकर इसे एक अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। अमेरिका भारत के साथ एक साझा डेवलपर इकोसिस्टम विकसित करना चाहता है, जो दोनों देशों के बीच मल्टी-लेवल तकनीकी साझेदारी की एक मजबूत नींव बनेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उच्च तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है, जिससे भविष्य में और अधिक साझेदारियों की उम्मीद है।

कुछ समय बाद कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जित करने लगेगा आर्कटिक क्षेत्रः शोध

जूनो

हाल ही गहरे अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आर्कटिक क्षेत्र की जमी हुई बर्फ के नीचे छिपा विशाल कार्बन भंडार आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन की चुनौती को और गंभीर बना सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो वर्तमान में वातावरण से कार्बन डाइआक्साइड सोखने वाला आर्कटिक क्षेत्र वर्ष 2050 के आसपास इस भूमिका को खो सकता है और इसके बजाय बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जित करने लगेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि ऐसा हुआ तो वैश्विक तापमान वृद्धि की रफ्तार तेज हो सकती है।

अब तक जलवायु माडल यह मानकर चलते रहे थे कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और उसके आसपास की भूमि लंबे समय तक कार्बन को अवशोषित करती रहेगी। बढ़ते तापमान के कारण बर्फ पिघलने के बावजूद वहां वनस्पतियों की वृद्धि अधिक कार्बन सोखने में मदद करेगी। इसी आधार

पर अनुमान लगाया गया था कि यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कुछ हद तक संतुलित करता रहेगा। हालांकि नई रिसर्च ने इस धारणा को चुनौती दी है। शोधकर्ताओं के अनुसार पुराने माडलों में जमीन की गहरी परतों में मौजूद कार्बन का सही आकलन नहीं किया गया था। साइबेरिया, अलास्का और कनाडा के बड़े हिस्सों में हजारों वर्षों से जमी हुई परमाफ्रास्ट परतों के नीचे भारी मात्रा में जैविक कार्बन दबा हुआ है।

यह कार्बन सतह से कई मीटर नीचे तक मौजूद है और अब तक बर्फ में कैद रहा है। वैज्ञानिकों ने एक उन्नत जलवायु माडल की मदद से इन गहरी परतों का अध्ययन किया। माडल में पिछले हिमयुग के बाद से जमा कार्बन और 1900 से 2014 तक के ऐतिहासिक आंकड़ों को शामिल किया गया। इसके आधार पर 2100 तक की संभावित परिस्थितियों का अनुमान लगाया गया। अध्ययन में सामने आया कि उत्तरी क्षेत्रों की मिट्टी में पहले की तुलना में कहीं अधिक कार्बन मौजूद है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, परमाफ्रास्ट तेजी से पिघल रही है। इसके पिघलने से मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीव सक्रिय हो जाते हैं और हजारों वर्षों से जमे जैविक पदार्थों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया से कार्बन डाइआक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें वातावरण में निकलती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 के दशक तक आर्कटिक क्षेत्र कार्बन सोखने की तुलना में अधिक कार्बन छोड़ने लगेगा।

शोधकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि वास्तविक खतरा उनके अनुमान से अधिक गंभीर हो सकता है। परमाफ्रास्ट का अचानक धंसना, थर्मोकार्स्ट झीलों का बनना, जंगलों में आग लगना और बर्फ की बदलती संरचना जैसी प्रक्रियाएं अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा दे सकती हैं। इनमें से कई कारकों को मौजूदा माडल में पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अध्ययन दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आर्कटिक में छिपा यह कार्बन भंडार वैश्विक जलवायु संकट को और गहरा कर सकता है।